

प्रेषक,

ओम प्रकाश,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक : 2 अप्रैल, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रजाखेत, नई टिहरी, के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017, शासनादेश संख्या: 206/XLI-1/15-मु0घो025(प्रशि0)/2012 दिनांक 25.03.2015, तथा 04/XLI-1/16-मु0घो0 25(प्रशि0)/2012 दिनांक 02.01.2016 एवं आपके पत्र संख्या 10474/डीटीईयू/प्रशि0/सूचना/2016 दिनांक 25.07.2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रजाखेत, नई टिहरी के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लि0, नई टिहरी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आंगणन ₹497.14लाख के सापेक्ष संस्तुत/अनुमोदित धनराशि ₹456.04लाख [₹432.17लाख सिविल कार्य + ₹23.87लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कार्य)] में से पूर्व निर्गत धनराशि ₹6.90लाख को घटाते हुये शेष धनराशि ₹449.14लाख में से वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्राविधानित धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त ₹180.00लाख एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राविधानित धनराशि में से द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त ₹70.84लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹257.74लाख को समायोजित करते हुए तृतीय किश्त के रूप में ₹47.16लाख (₹सैंतालिस लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नियमानुसार धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. यदि वर्तमान में स्वीकृत धनराशि को विभाग अथवा कार्यदायी संस्था द्वारा कोषागार से आहरित कर बैंक खाते में रखा जाता है तो उस पर अर्जित ब्याज को यथासमय राजकोष/कोषागार की सुसंगत प्राप्ति शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
  2. शेष शर्तें/प्रतिबन्ध उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या : 206/XLI-1/15-मु0घो0 25(प्रशि0)/2012 दिनांक 25.03.2015, एवं 04/XLI-1/16-मु0घो0 25(प्रशि0)/2012 दिनांक 02.01.2016 के अनुसार यथावत लागू होंगे।
  3. उपरोक्त प्रयोजन कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या सहित एवं अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर अवशेष धनराशि का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के 'अनुदान संख्या 16' के 'आयोजनागत/पूँजीगत' पक्ष के लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-001-निर्देशन तथा प्रशासन-07-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण-00 के अन्तर्गत मानक मद "24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में [www.cts.uk.gov.in](http://www.cts.uk.gov.in) से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संलग्नक-1 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
4. यह आदेश वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश 312/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

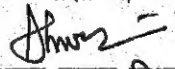
( ओम प्रकाश )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 306 (1)/XLI(1)/17-मु0घो0 25(प्रशि0)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4. जिलाधिकारी नई टिहरी/नैनीताल।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हल्द्वानी/नई टिहरी।
7. वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी-नैनीताल।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रजाखेत, नई टिहरी।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
11. परियोजना प्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लि0, नई टिहरी।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
( अनूप कुमार मिश्रा )  
अनु सचिव।